समर एक्सप्रेस

www.summerexpress.in

द SUMMER न्यूज़

सूर्योदय सुबह 6:06 बजे
सूर्यास्त शाम 6:51 बजे

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

• साल-1 • अंक-213 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • वीरवार 9 अप्रैल 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एजीक्यूटिव एडिटर : चंदन स्वप्निल

40वें दिन US-ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर

एजेंसी | तेहरान/वॉशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दो हफ्ते के सीजफायर को स्वीकार तो किया है, लेकिन साफ कहा है कि इसे "युद्ध का अंत" नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही, अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होने की संभावना जताई गई है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका भी सामने आई है।

ईरान का 10-पॉइंट प्रस्ताव

इस पूरे समझौते के केंद्र में ईरान का 10-पॉइंट प्रस्ताव है, जिसे आगे की बातचीत का आधार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में अमेरिका और इजराइल से हमले पूरी तरह रोकने की गारंटी, सभी आर्थिक और परमाणु प्रतिबंध हटाने की मांग, करीब 100 अरब डॉलर की जब्त संपत्ति वापस करने की शर्त, खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना की वापसी, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज पर ईरान का नियंत्रण, जहाजों की आवाजाही पर निगरानी और शुल्क वसूली, पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति व्यवस्था जैसी प्रमुख बातें शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि अमेरिका फिलहाल अपने हमले आगे नहीं बढ़ाएगा, बशर्ते ईरान युद्धविराम का पालन करे और होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही सामान्य बनाए रखे। हालांकि, जमीन पर तस्वीर अभी भी पूरी तरह शांत नहीं दिख रही। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे। ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी।

भारत ने ईरान में नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की

कई रिपोर्टों में खाड़ी क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में अलर्ट, हमलों और तनाव जारी रहने की बात कही गई है। इसी वजह से भारत ने एहतियाती रुख अपनाया है। तेल बाजार और वैश्विक व्यापार के लिए अहम होर्मुज जलडमरूमध्य इस समझौते का प्रमुख बिंदु बना हुआ है। यही कारण है कि भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय एडवाइजरी का संदेश साफ है कि सीजफायर घोषित जरूर हुआ है, लेकिन हालात अब भी नाजुक हैं, इसलिए ईरान या आसपास के संवेदनशील इलाकों में मौजूद भारतीय नागरिक किसी भी तरह की ढील न बरतें। अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम की घोषणा के बावजूद भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय मिशन ने नागरिकों से कहा है कि वे हालिया सुरक्षा हालात को देखते हुए तुरंत और बेहद सावधानी के साथ अपनी यात्रा योजनाएं तय करें।

ईरान सीजफायर में चीन की अहम भूमिका, ट्रंप ने भी दिए संकेत

नई दिल्ली | अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो सप्ताह के युद्धविराम को लेकर अब चीन की कूटनीतिक भूमिका चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजिंग ने पर्दे के पीछे सक्रिय रहकर तेहरान को बातचीत के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि चीन ने ईरान को वार्ता की टेबल तक लाने में मदद की। हालांकि, चीन ने आधिकारिक तौर पर इस भूमिका की पुष्टि नहीं की है।

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद तेहरान में जमा लोग खुशी जाहिर करते हुए।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में रणनीतिक तरीके से हस्तक्षेप किया, ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को रोका जा सके।

बताया जा रहा है कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने से जुड़े प्रस्ताव पर चीन और रूस ने वीटो किया था। साथ ही, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें युद्ध रोकने और समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने की बात कही गई थी। ईरान ने यह भी संकेत दिया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर लगने वाला शुल्क चीनी मुद्रा में लिया जा सकता है। इसे वैश्विक स्तर पर डॉलर के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

इजराइल की लेबनान पर बमबारी, कहा- सीजफायर सिर्फ ईरान तक सीमित

तेल अवीव/बेरूतः अमेरिका-ईरान युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने साफ कर दिया कि यह समझौता लेबनान पर लागू नहीं होता। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच जो दो हफ्ते का विराम तय हुआ है, वह हिज्बुल्लाह के खिलाफ चल रही इजराइली सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकता।

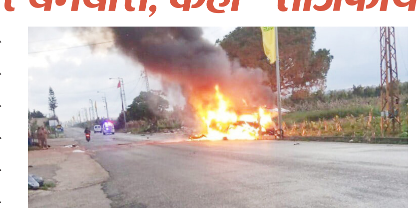

द. लेबनान के टायर जिले में एक वाहन में मौजूद आतंकियों को निशाना बनाकर इज़राइल ने हमला किया।

इसी बीच बुधवार को दक्षिण लेबनान में इजराइली कार्रवाई फिर तेज हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, इजराइली सेना ने टायर शहर के पास एक इमारत को खाली करने की चेतावनी जारी की और दक्षिणी लेबनान में नए हमले किए। इस कदम ने यह साफ कर दिया कि क्षेत्रीय तनाव कम होने के दावों के बावजूद लेबनान मोर्चा अब भी सक्रिय है। इज़राइल ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता सिर्फ ईरान के साथ संघर्ष तक सीमित है और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका में यह संकेत दिया था कि संघर्षविराम व्यापक हो सकता है, लेकिन इजराइल ने सार्वजनिक रूप से उस दावे से दूरी बना ली। उधर, कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि युद्धविराम की शर्तों को लेकर अभी भी भ्रम बना हुआ है और अलग-अलग पक्ष उसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं।

तेल और बाजार पर असर

तनाव कम होने के संकेतों के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है और वैश्विक बाजारों में सुधार देखने को मिला है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीजफायर अभी नाजुक स्थिति में है और इसकी स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

पाक की भूमिका को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली | कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम में पाकिस्तान की कथित भूमिका को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि यह

घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और उनकी 'पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी' की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच हुए सीजफायर का दुनिया स्वागत कर रही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आना भारत की कूटनीतिक स्थिति के लिए झटका है।रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत छवि पर आधारित रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करने के दावे भी अब सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार ने गाजा मुद्दे और वेस्ट बैंक में हालात पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जिससे भारत की पारंपरिक संतुलित विदेश नीति कमजोर होती नजर आई। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की रणनीति भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है। एक कमजोर आर्थिक स्थिति वाला देश ऐसी भूमिका निभा रहा है, जिससे भारत की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठते हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

कांग्रेस की नेता मोहसिना का निधन

नई दिल्ली| पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई ने बुधवार सुबह आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक उन्होंने नोएडा में देर रात करीब 3 बजे आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई उन्हें याद कर रहा है। मोहसिना किदवई भारतीय राजनीति की एक मजबूत और सम्मानित शख्सियत रही हैं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं।

मिसरी तीन दिन के अमेरिका दौरे पर

वॉशिंगटन| भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी तीन दिन के अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। वॉशिंगटन पहुंचने पर उनका स्वागत अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने किया। क्वात्रा ने कहा कि यह दौरा भारत-अमेरिका साझेदारी के "फुल ब्रेड्थ" की समीक्षा का मौका देगा और व्यापार, रक्षा, तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा और सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। दौरे के दौरान विक्रम मिसरी अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

इराक में किडनैप अमेरिकी पत्रकार रिहा

बगदाद| इराक में किडनैप की गई अमेरिकी पत्रकार शेली किट्लेसन को रिहा कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। किट्लेसन का मार्च के अंत में बगदाद में अपहरण हुआ था। इराक सरकार और शिया नेताओं के दबाव के बाद ईरान समर्थित काताइब हिजबुल्लाह ने उनकी रिहाई की घोषणा की। रुबियो ने बताया कि पेंटागन, FBI और इराक की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने मिलकर किट्लेसन की रिहाई सुनिश्चित की। काताइब हिजबुल्लाह ने मंगलवार को कहा था कि वह किट्लेसन को रिहा करेगा, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें तुरंत इराक छोड़ना होगा।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिर्पोटर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 7986630191 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

7 देशों के स्कूल 17 तक अपलोड करें 12वीं के अंकः सीबीएसई

■ **देरी या गलती पर नहीं मिलेगा दूसरा मौका, तय समय सीमा के बाद पोर्टल होगा बंद**

नई दिल्लीः सीबीएसई ने पश्चिम एशिया के सात देशों में स्थित अपने संबद्ध स्कूलों के लिए कक्षा 12वीं के अंकों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि स्कूलों को 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच ही छात्रों के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

सीबीएसई ने कहा है कि तय समय सीमा के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और न ही अंकों में सुधार का कोई अवसर मिलेगा। बोर्ड के अनुसार, स्कूल केवल निर्धारित अवधि के भीतर ही डेटा अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे समय पर प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि इसी के आधार पर परिणामों की समयबद्ध घोषणा संभव होगी।

इस बार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अंकों की एंट्री में कोई त्रुटि होती है, तो उसे बाद में ठीक करने की अनुमति नहीं होगी। यानी एक बार अपलोड किया गया डेटा अंतिम

माना जाएगा। इसलिए स्कूलों को अपलोड से पहले पूरी जांच करने की सलाह दी गई है।

अंकों की एंट्री के लिए सीबीएसई एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जो 8 अप्रैल से सक्रिय होगा। स्कूलों को अपने लॉगिन के जरिए इसी पोर्टल पर डेटा अपलोड करना होगा, जिससे प्रक्रिया डिजिटल और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सके।

यह निर्देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान में स्थित सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय स्कूल संचालित होते हैं, जहां हर साल हजारों छात्र 12वीं की परीक्षा देते हैं।

सीबीएसई का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि छात्रों के परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।

असम में विधानसभा का प्रचार थमा, चुनाव आज

नई दिल्लीः असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार 7 अप्रैल की शाम थम गया है और अब राज्य की सभी 126 सीटों पर वीरवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतग णना 4 मई 2026 को होगी।

इस चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2,50,54,463 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1।25 करोड़ से अधिक पुरुष और लगभग इतनी ही महिला मतदाता शामिल हैं, साथ ही 318 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हैं। इसके अलावा 63,423 सर्विस वोटर भी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। युवा मतदाताओं की संख्या भी खास है—18 से 19 वर्ष के 6।42 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र के 2।5 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक और करीब 2।05 लाख दिव्यांग मतदाता भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दी है। अब तक 26 हजार से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक और 8 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

चुनाव की निगरानी के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल के नेतृत्व में पूरी टीम सक्रिय है और कानून-व्यवस्था तथा चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है।

मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए SVEEP कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में अभियान चलाए गए हैं। साथ ही 31,490 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे मतदान प्रक्रिया की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

ब्याज दरों में नहीं किया हुआ कोई बदलाव, रेपो रेट 5.25% कायम

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला लिया।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि यह निर्णय मौजूदा महंगाई दर और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह इस वित्तीय वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा भी है।

सरकार द्वारा हाल ही में तय किए गए नए महंगाई लक्ष्य के तहत आरबीआई को मार्च 2031 तक खुदरा महंगाई दर को 4 प्रतिशत बनाए रखना है।

फरवरी महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.21 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के लक्ष्य के करीब है। ऐसे में फिलहाल ब्याज दरों में कटौती न करने का फैसला लिया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच करीब छह सप्ताह तक चले संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई और

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों पर महंगाई का दबाव बढ़ा।

इसके अलावा, संघर्ष के दौरान भारतीय रुपया भी दबाव में रहा और डॉलर के मुकाबले 4 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। इससे आयात महंगा हो गया और महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हुई। हालांकि, युद्धविराम के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और रुपया 50 पैसे मजबूत होकर 92.56 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है।

पिछले महीने रुपया अपने ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिरकर 95 प्रति डॉलर के पार चला गया था। RBI का मानना है कि वैश्विक हालात में स्थिरता आने से आगे आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

पेज 1 एंकर स्टोरी

पंजाब पुलिस ने जारी किया 17 सूत्रीय सर्कुलर

सबूत के बिना युवाओं की गिरफ्तारी पर रोक

चंडीगढ़ः पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद पंजाब पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ निर्देश जारी किए हैं कि साफ-सुथरे बैकग्राउंड वाले युवाओं के खिलाफ बिना ठोस और निष्पक्ष सबूत के कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

17 बिंदुओं वाले इस सर्कुलर में पुलिस ने कहा है कि केवल "गुप्त सूचना" के आधार पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज करने या गिरफ्तारी करने से बचा जाए। हाई कोर्ट ने इसे "औपनिवेशिक दौर की पुलिसिंग" बताते हुए फटकार लगाई थी।

सर्कुलर के अनुसार, आमतौर पर संदिग्ध युवाओं की पहचान मीडिया में उजागर नहीं की जाएगी और जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, उनके शैक्षणिक संस्थानों या नियोक्ताओं को भी जांच की जानकारी नहीं दी जाएगी। खासतौर पर 18 से 20 वर्ष के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि जांच के दौरान उनकी पढ़ाई, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर अनावश्यक असर न पड़े।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी डिजिटल उपकरण—जैसे मोबाइल या लैपटॉप सिर्फ जरूरी डेटा निकालने तक ही जब्त किए जाएं और बाद में तुरंत वापस कर दिए जाएं, ताकि पढ़ाई और पेशेवर

गतिविधियों में बाधा न आए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पुलिस थानों में पेशी के समय का निर्धारण ऐसे किया जाए जिससे कक्षाओं, परीक्षाओं और शुरुआती करियर पर असर न पड़े।

गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के "अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य" फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि केवल अपराध संज्ञेय होने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जांच अधिकारी को गिरफ्तारी की आवश्यकता के ठोस कारण दर्ज करने होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर बिना स्वतंत्र पुष्टि के किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। पुलिस को मोबाइल, वाट्सएप चैट, लोकेशन डेटा या अन्य ठोस साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर के अनुसार, यदि समीक्षा के बाद साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं तो बिना देरी के नाम हटाने या केस बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के समक्ष यह चिंता जताई गई थी कि पहली बार संदेह के दायरे में आए युवाओं का भविष्य अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बर्बाद हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सर्कुलर जारी किया गया है, जो पुलिसिंग में संवेदनशीलता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

क्या है इसका मतलब?

इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच प्रक्रिया खुद सजा न बन जाए। युवाओं का नाम सार्वजनिक न करना, पढ़ाई में बाधा न डालना, डिजिटल उपकरण लंबे समय तक जब्त न रखना और बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारी न करना ये सभी कदम युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माने जा रहे हैं।